[2022] [19 एस.सी.आर. 400

अखिलेश प्रसाद

बनाम

झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य

(2022 की सिविल अपील संख्या 3180)

अप्रैल 26, 2022

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भट्ट और पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 - धारा 73 और 74 - राज्य के पुनर्गठन के बाद सेवाएं - अपीलार्थी ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत तत्कालीन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1994 में आयोजित सहकारी विकास अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण की - बिहार राज्य को उत्तराधिकारी राज्य झारखण्ड में विभाजित किया गया था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के परिणामस्वरूप बिहार राज्य और झारखंड का नवगठित राज्य बिहार राज्य के विभाजन के बाद, अपीलार्थी की सेवा झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य को आवंटित की गई थी और तब से वह झारखंड राज्य की सेवा में थे - सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से उप-कलेक्टरों के पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके अनुसार आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो झारखंड राज्य में तैनात उप-मंडल अधिकारी से प्राप्त उपयुक्त जाति प्रमाण पत्र जमा करते हैं - विभागीय परीक्षा में एसटी श्रेणी के लिए कट-ऑफ के मुकाबले अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद अपीलार्थी को असफल घोषित किया गया था - अपीलार्थी ने एक रिट याचिका दायर करके अपने गैर-चयन को चुनौती दी जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले से ही सहकारी विभाग में एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में काम कर रहा था - वह विभाजन के बाद भी अपनी आरक्षित श्रेणी को अपने साथ ले गया - इस प्रकार, राज्य ने

याचिकाकर्ता को अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रूप में स्वीकार किया, जबकि वह राज्य के तहत सहकारी विभाग में काम कर रहा था, लेकिन उसे आरक्षित श्रेणी यानी के रूप में नहीं माना। सीमित परीक्षा के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति, स्वीकार्य नहीं है और न ही कानून की नजर में उसका अधिकार - हालांकि, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता विज्ञापन की शर्त संख्या 13 का पालन करने में विफल रहा था और चूंकि किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था कि वह झारखंड राज्य में एसटी (गोंड) श्रेणी से संबंधित था, इसलिए अपीलार्थी को इस श्रेणी का पात्र उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता था - सीमित विभागीय परीक्षा के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित श्रेणी से संबंधित - अपील पर अभिनिर्धारित उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति। (अपने और पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्ति के लिए) उच्चतम न्यायालय ने पंकज कुमार के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि जो कर्मचारी पुनर्गठन के बाद उत्तराधिकारी राज्य के अधीन सेवा का विकल्प चुनते हैं, उनकी वर्तमान सेवा शर्तें उनके नुकसान के लिए भिन्न नहीं होंगी और अधिनियम की धारा 73 के आधार पर संरक्षित होंगी - इस शर्त के अधीन कि ऐसा व्यक्ति दोनों उत्तराधिकारी राज्यों में एक साथ आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा, ऐसे कर्मचारी न केवल उस उत्तराधिकारी राज्य की सेवा में आरक्षण के लाभ का दावा करने के हकदार होंगे, जिसे उन्होंने चुना था और आवंटित किया गया था, बल्कि वे आरक्षण के लाभ के साथ किसी भी बाद की खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के भी हकदार होंगे - इसलिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को अनुमति देने में सही था - उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं ठहराया कि सीमित विभागीय परीक्षा खुले बाजार से सीधी भर्ती के अलावा और कुछ नहीं थी - रवींद्र भट, न्यायमूर्ति। (सहमति) संसद की ओर से यह दायित्व है कि वह नए पुनर्गठित राज्यों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर ऐसे व्यक्तियों की स्थिति के बारे में, किस प्रकार की सुरक्षा के बारे में स्पष्टता प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उनकी स्थिति खराब न हो।

अपील को स्वीकार करते हुए,

अदालत ने कहाः उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति के मुताबिक। [अपने और पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, न्यायमूर्ति के लिए]

1. जो कर्मचारी पुनर्गठन के बाद उत्तराधिकारी राज्य के तहत सेवा का विकल्प चुनते हैं, उनकी मौजूदा सेवा शर्तें उनके नुकसान के लिए भिन्न नहीं होंगी और अधिनियम की धारा 73 के आधार पर संरक्षित होंगी। इसके अलावा, इस शर्त के अधीन कि ऐसा व्यक्ति दोनों उत्तराधिकारी राज्यों में एक साथ आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा, ऐसे कर्मचारी न केवल उस उत्तराधिकारी राज्य की सेवा में आरक्षण के लाभ का दावा करने के हकदार होंगे, जिसे उन्होंने चुना था और आवंटित किया गया था, बल्कि वे आरक्षण के लाभ के साथ किसी भी बाद की खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के भी हकदार होंगे। [कंडिका 17][415-ख-ग]

2. पंकज कुमार के मामले में निर्णय इस न्यायालय द्वारा 19.8.2021 को दिया गया था, जबकि वर्तमान में चुनौती के तहत निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा 12.5.2021 को दिया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय का लाभ नहीं मिला। पंकज कुमार में कानून का निपटारा होने के बाद, अपील के तहत दिए गए फैसले को पंकज कुमार में दिए गए फैसले के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए यह मायने नहीं रखेगा कि सीमित विभागीय परीक्षा की प्रकृति को सीधी भर्ती के रूप में लिया जाना है या नहीं, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पाया है। [कंडिका 18] [415-घ]

3. सेवा में तुलनात्मक रूप से कनिष्ठ होने वाले मेधावी उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए, सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से अवसर की एक खिड़की खोली जाती है। जो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वे त्वरित पदोन्नति के हकदार होते हैं। यह प्रक्रिया आंदोलन के चरित्र को उच्च पद पर नहीं बदलती है और यह एक प्रचार चैनल बना हुआ है। इसलिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश रिट याचिका को अनुमति देने में सही था। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के रेखांकित भाग से पता चलता है कि मामले पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह निष्कर्ष निकालकर न्यायसंगत नहीं माना कि सीमित विभागीय परीक्षा खुले बाजार से सीधी भर्ती के अलावा और कुछ नहीं थी। इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है और डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है, जबकि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया जाता है। [कंडिका 20 और 24][417-छ-ज; 418-क-ख, ज]

एस. रवींद्र भाट, न्यायमूर्ति के मुताबिक (सहमति)

1. मेरी सुविचारित राय में, यह देखते हुए कि राज्यों का पुनर्गठन होता है राजनीतिक मांगों के परिणामस्वरूप, या क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के रूप में, इस तरह की घटना में व्यक्ति (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्य) की कोई एजेंसी नहीं है। यह स्थिति उस स्थिति से मौलिक रूप से अलग है, जहां ऐसे समुदाय का कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राज्य से बाहर के अवसरों की तलाश करता है, जिस स्थिति में मर्री चंद्र शेखर राव का नियम लागू होगा। नतीजतन, संसद की ओर से यह दायित्व है कि वह नए पुनर्गठित राज्यों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर ऐसे व्यक्तियों की स्थिति के बारे में, किस प्रकार की सुरक्षा के बारे में स्पष्टता प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि वे इसके परिणामस्वरूप बदतर स्थिति में न हों। मर्री चंद्र शेखर राव में एक अलग तरह के अनैच्छिक आंदोलन पर भी विचार किया गया था, जहां इस अदालत ने वास्तव में संसद (या संबंधित राज्य विधानसभाओं) को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बच्चों की भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रावधान करने के लिए सराहना की थी, जिन्हें सार्वजनिक रोजगार की अपनी शर्तों के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता है। इसके अलावा, स्पष्टता और सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य, आम तौर पर बोलना सुसंगत होना चाहिए - एक राज्य के पुनर्गठन के मामले में, सुरक्षा दूसरे राज्य के पुनर्गठन के मामले में अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 14 और 15 (1) के आदेश को हरा देगा (बाद के मामले में, संभवतः जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है) मेरी राय में, यह कर्तव्य संविधान के भाग । (अनुच्छेद 1 से 4) अनुच्छेद 14,15 (1) 341 और 342 के सह-संयुक्त पठन और इस व्यापक चिंता से उत्पन्न होता है कि व्यक्ति की स्थिति, उसके या उसके द्वारा बनाए गए व्यवधान के कारण नहीं, बदतर नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में संसद का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना एक संवैधानिक दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति या समूह वंचित ना रहे। [कंडिका 10][425-क -च]

पंकज कुमार बनाम झारखंड राज्य और अन्य। (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 616 - पर भरोसा किया गया।

सुधाकर विट्ठल कुम्भारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2001 (4) बीओएमसीआर 582: [2003] 5 अनुपूरक एससीआर 746; स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। [1994] 1 अनुपूरक एससीआर 71; उ.प्र. लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद बनाम संजय कुमार सिंह (2003) 7 एससीसी 657; झारखंड राज्य बनाम भदेय मुंडा (2014)10 एससीसी 398: [2014] 7 एससीआर 765; मैसूर राज्य बनाम जी. बी. पुरोहित (1967) 1 एसएलआर

753; कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अपर आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य, (1994) 6 एससीसी 241: [1994] 3 सप्ल. एससीआर 50; ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (2002) 4 एससीसी 247; मैरी चंद्रशेखर राव बनाम डीन सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज (1990) 3 एससीसी 130: [1990] 2 एससीआर 843; (ख) महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी कार्य समिति और महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी कार्य समिति के गठन के संबंध में गठित की गई है एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1994) 5 एससीसी 244: [1994] अनुपूरक एससीआर 714 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

[2003] अनुपूरक 5 एससीआर 746 संदर्भित कंडिका 16

[1994] अनुपूरक 1 एससीआर 71 संदर्भित कंडिका 16

[1994] 3 सप्ल. एससीआर 50 संदर्भित कंडिका 16

[1994] अनुपूरक एससीआर 714 संदर्भित कंडिका 6

[2014] 7 एससीआर 765 संदर्भित कंडिका 7

[1990] 2 एससीआर 843संदर्भित कंडिका 8

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 3180 की सिविल अपील संख्या 2022।

2017 के एलपीए संख्या 609 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.05.2021 से।

मनोज टंडन, कुमार शिवम, मयंक सप्रे, रोहित अनिल राठी, अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट्स।

अरुणाभ चौधरी, सीनियर एडवोकेट, हिमांशु शेखर, पार्थ शेखर, सुश्री प्रज्ञा बघेल, कुमार अनुराग सिंह, अभिषेक रॉय, सुश्री तूलिका मुखर्जी, अक्षत सिंह, जैन खान, संजीव सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेटस।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गए था

उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति

लीव की अनुमति दी गयी

2. यह अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 12.05.2021 को चुनौती देती है 2017 के एलपीए नंबर 609 में।

3. सहकारिता विकास अधिकारियों के पदों को भरने के लिए वर्ष 1994 में आयोजित स्नातक स्तरीय (विशेष) प्रतियोगिता परीक्षा में तत्कालीन बिहार लोक सेवा आयोग ने दिनांक 24.07.1995 के पत्र द्वारा मेरिट सूची में क्रम संख्या 98 पर रहने वाले अपीलार्थी के नाम की अनुसूचित जनजाति ('एसटी', संक्षेप में) श्रेणी के तहत अनुशंसा की थी। यह दावा कि अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति श्रेणी (गोंड) से संबंधित था, जांच अधिकारी, सोनपुर (सारण) द्वारा 03.06.1995 को जारी किए गए एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित था, जो अब राज्यों के पुनर्गठन के बाद नए गठित झारखण्ड राज्य में आता है। बाद में, अपीलकर्ता सहित चयनित उम्मीदवारों को दिनांक 10.11.1995 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। सेवा पुस्तिका में उपयुक्त प्रविष्टि अपीलकर्ता का नाम और श्रेणी एसटी (गोंड) से संबंधित दर्शाती है।

4. बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 [2000 का अधिनियम 30] (संक्षेप में 'अधिनियम') के परिणामस्वरूप तत्कालीन बिहार राज्य को विभाजित किया गया था, जो 15.11.2000 को लागू हुआ था। पूर्ववर्ती बिहार राज्य को उत्तरवर्ती राज्य में विभाजित किया गया था अर्थात बिहार राज्य में 38 जिले हैं और नवगठित झारखंड राज्य जिसमें 18 जिले शामिल हैं। अधिनियम की धारा 73 और 74 निम्नानुसार हैं: -

“ 73. सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंध--(1) धारा 72 की कोई बात संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन को नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी : बशर्ते कि धारा 72 के तहत बिहार राज्य या झारखंड राज्य को आवंटित किए गए समझे गए किसी व्यक्ति के मामले में नियत दिन से ठीक पहले लागू सेवा की शर्तें केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा उसके नुकसान के लिए भिन्न नहीं होंगी। (2) किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन से पूर्व की सभी सेवाएं- (क)

यदि वह धारा 72 के अधीन किसी राज्य को आबंटित किया गया समझा जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह उस राज्य के कार्यकलाप के संबंध में प्रदान की गई है; (ख) यदि वह झारखंड के प्रशासन के संबंध में संघ को आबंटित किया गया समझा जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह संघ के कार्यकलाप के संबंध में उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए दिया गया है। (3) किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में धारा 72 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

74. अधिकारियों का उसी पद पर बने रहने के बारे में उपबंध--प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन से ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के कार्यकलाप के संबंध में किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उस दिन किसी उत्तरवर्ती राज्य के भीतर आता है, किसी पद या पद पर आसीन या कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस उत्तरवर्ती राज्य में वही पद या पद धारण करता रहेगा, और उस दिन से और उस दिन से, उस उत्तराधिकारी राज्य में सरकार या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पद या कार्यालय में विधिवत नियुक्त किया गया माना जाएगा: बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी सक्षम प्राधिकारी को रोकने के लिए नहीं समझा जाएगा, नियत दिन से, ऐसे व्यक्ति के संबंध में कोई आदेश पारित करने से इस तरह के पद या कार्यालय में निरंतरता को प्रभावित करता है।

5. राज्यों के पुनर्गठन के बाद, अपीलकर्ता की सेवा झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य को आवंटित की गई थी और तब से अपीलकर्ता झारखंड राज्य की सेवा में है।

6. 14.08.2008 को झारखंड राज्य के तहत सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में प्रमुख सचिव, झारखंड सरकार द्वारा सभी विभागों के सचिवों को एक पत्र जारी किया गया था। पत्र के कंडिका 1 और 4 निम्नानुसार थे: -

"महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में, मुझे, जैसा कि निर्देश दिया गया है, निवेदन करना है कि, कुछ विभाग निम्नलिखित बिंदुओं पर इस विभाग से दिशानिर्देश/परामर्श की अपेक्षा कर रहे हैं:

पदोन्नति में आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को ही दिया जाए जनजातियां यदि वे झारखंड राज्य के स्थायी निवासी हैं, यहां तक कि अगर वे अविभाजित बिहार में नियुक्त किए गए थे।

4. इस संबंध में, राज्य सरकार ने उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नानुसार निर्णय लिया है:

"आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी, जिन्हें नियुक्त किया गया था राज्य के गठन से पूर्व आरक्षित श्रेणियों और कैडर के विभाजन के आधार पर झारखंड राज्य में तैनात किए गए थे और वे बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, अप्रभावित रहेंगे और उन्हें आरक्षित श्रेणी के सरकारी कर्मचारी माना जाएगा।

7. सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से उप कलेक्टरों के पदों को भरने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग ('आयोग', संक्षेप में) द्वारा 2010 का विज्ञापन संख्या 9 जारी किया गया था। तथापि, दिनांक 09-10-2010 को जारी उक्त विज्ञापन में यह निर्धारित किया गया था कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो झारखंड राज्य में तैनात उपखण्ड अधिकारी से उपयुक्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। अपीलकर्ता ने सीमित विभागीय परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की थी, जिसे रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, झारखंड के कार्यालय द्वारा आयोग को भेज दिया गया था।

8. 04.05.2013 को घोषित परीक्षा परिणामों में, अपीलकर्ता को असफल घोषित किया गया था, हालांकि उसने एसटी श्रेणी के लिए कट-ऑफ 113.70 की तुलना में 123.68 अंक प्राप्त किए थे।

9. अपीलकर्ता ने 2013 की रिट याचिका संख्या 3480 दायर करके अपने गैर-चयन को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 22.09.2017 द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अनुमति दी थी: -

“8. उपर्युक्त उपबंध से यह पूर्णत स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक झारखंड राज्य की सीमित परीक्षा का संबंध है, आरक्षण का लाभ ऐसे अभ्यथयों को भी दिया जाए जो एकीकृत राज्य बिहार के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी के पद पर जन्मे हों। डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति नई नियुक्ति हो सकती है, लेकिन उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया को देखना होगा। यह परीक्षा एक सामान्य खुली प्रतियोगी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह केवल झारखंड सरकार के सेवारत उम्मीदवारों के लिए खुली है। इस प्रकार, जो व्यक्ति झारखंड राज्य के तहत नियोजित नहीं हैं, वे उक्त परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं हैं। इसका अर्थ है कि केवल एक सरकारी कर्मचारी ही उक्त परीक्षा में बैठने का हकदार है। उक्त कर्मचारी, यदि परीक्षा में सफल होता है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो राज्य के साथ उसकी पिछली सेवाओं

को भी सभी उद्देश्यों के लिए गिना जाता है। इस प्रकार, यह उनकी पहले की सेवा की निरंतरता में है। इस मामले में, याचिकाकर्ता पहले से ही सहकारी विभाग में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में काम कर रहा था और उसके बाद झारखंड राज्य के तहत सहकारी विभाग में अपने रोजगार के आधार पर, वह परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य था। माना जाता है कि वह आरक्षित श्रेणी के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं और राज्य के विभाजन के बाद उन्हें झारखंड कैडर आवंटित किया गया था। विभाजन के बाद भी वह अपनी आरक्षित श्रेणी अपने साथ ले गए। इस प्रकार, दिनांक 14.08.2008 का संकल्प संख्या 4722 याचिकाकर्ता पर लागू होता है। राज्य याचिकाकर्ता को अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रूप में स्वीकार करता है, जबकि वह राज्य के तहत सहकारी विभाग में काम कर रहा है, लेकिन सीमित परीक्षा के उद्देश्य से उसे आरक्षित श्रेणी यानी अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं मानना इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है और न ही उसकी नजर में उसकी धारणा। नियम - नियुक्त को नई नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता, राज्य के पुनर्गठन के बाद, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में झारखंड राज्य कैडर आवंटित किया गया था। इस प्रकार, सेवा के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में उसकी स्थिति को बनाए रखा जाना है। इस प्रकार, उत्तरदाताओं का दावा है कि याचिकाकर्ता को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता है कानून की नजर में ठीक। इसी तरह के विचार को इस न्यायालय ने 2013 की रिट याचिका (एस) संख्या 488 में दोहराया है। डिवीजन बेंच में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया है, इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिली है क्योंकि वे अलग-अलग आधार पर थे और वर्तमान मामला कट-ऑफ तारीख के बाद सी प्रमाण पत्र जमा करने का मामला नहीं है।

9. उपरोक्त नियमों, दिशानिर्देशों और न्यायिक निर्णयों के संचयी प्रभाव के रूप में, मैं प्रतिवादी - जे.पी.एस.सी. को विज्ञापन संख्या 09/10 के अनुसार डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देता हूं, जैसा कि आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति)। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे डिप्टी कलेक्टर के पद पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें, यदि वह इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अपनी श्रेणी के अन्य उम्मीदवारों के साथ उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर विचार क्षेत्र के भीतर पाया जाता है। (महत्व दिया)

10. आयोग के साथ-साथ झारखंड राज्य ने असंतुष्ट होने के कारण, एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए क्रमशः 2017 की एलपीए संख्या 609 और 2018 की एलपीए संख्या 164 को प्राथमिकता दी। यह प्रस्तुत किया गया था कि विज्ञापन की शर्त के रूप में संख्या 13 द्वारा अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र, साथ ही निवास का प्रमाण झारखंड राज्य के अधिकार क्षेत्र में तैनात उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जाना था, और अपीलकर्ता ऐसी आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा है, उसे झारखंड राज्य में आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

जवाब में, अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि सीमित प्रतियोगी परीक्षा को एक नई नियुक्ति नहीं माना जा सकता है; बल्कि यह उच्च पद पर पदोन्नति का मामला था और इस तरह अपीलकर्ता जो पहले से ही झारखंड राज्य के तहत सेवा में था, अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी की पेशकश करने का हकदार था।

11. उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थे:-

"(i) क्या सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति एक नई नियुक्ति है या पदोन्नति के माध्यम से ?

(ii) क्या बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 का प्रावधान अधिनियम की धारा 72(2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेश के बाद सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने वाले चयन की प्रक्रिया में लागू होगा?

(iii) क्या विज्ञापन की शर्तों को उन उम्मीदवारों द्वारा उल्लंघन करने की अनुमति दी जा सकती है जिन्होंने चयन की प्रक्रिया में भाग लिया है लेकिन असफल घोषित किए हैं?

(iv) क्या नई नियुक्ति के मामले में आरक्षण को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 के प्रावधान को लागू करने के लिए सेवा की शर्त कहा जा सकता है?

12. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पाया कि सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले 25% पद नई नियुक्ति के माध्यम से होंगे और इस तरह, अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 72 और 73 के प्रावधानों पर भरोसा नहीं कर सकता है। चूंकि अपीलकर्ता विज्ञापन की शर्त संख्या 13 का पालन करने में विफल रहा था और चूंकि किसी भी सक्षम

प्राधिकारी द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था कि वह झारखंड राज्य में एसटी (गोंड) श्रेणी से संबंधित है, अपीलकर्ता को सीमित विभागीय परीक्षा के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं कहा जा सकता है।

13. निर्णय की शुद्धता वर्तमान में चुनौती के अधीन है।

14. श्री मनोज टंडन, अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं अन्य बातों के साथ-साथ कि:-

(क) अनुसूचित जनजाति संविधान [अनुसूचित जनजातियां] आदेश, 1950 का हिस्सा है जो नवगठित राज्य बिहार के संबंध में क्रम संख्या 10 पर और झारखंड राज्य के संबंध में क्रम संख्या 11 पर है।

(ख) अपीलकर्ता तत्कालीन अविभाजित राज्य बिहार की सेवा में रहा हो और उसकी सेवाएं रही हों झारखंड राज्य को आबंटित निधियों के मामले में यह अधिनियम की धारा 72 और 73 के अंतर्गत लाभों और संरक्षण का हकदार है।

(ग) अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित व्यक्ति का दर्जा उसे झारखंड राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में भी पदोन्नति में आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार बनाएगा

(घ) सीमित विभागीय परीक्षा की प्रकृति त्वरित पदोन्नति के अलावा और कुछ नहीं है; इसमें पदोन्नति के नियमित तरीके की तुलना में जो सक्षम हैं और सीमित विभागीय परीक्षा में मेधावी पाए जाते हैं, उन्हें पदोन्नत भले ही वे तुलनात्मक रूप से जूनियर हों।

(ड) सीमित विभागीय परीक्षा केवल उन्हीं लोगों द्वारा ली जा सकती है जो इस समय सेवा में हैं और खुले बाजार से किसी सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

(च) इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। पंकज कुमार बनाम झारखण्ड राज्य[2]

15. श्री अरुणाभ चौधरी, झारखंड राज्य के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री हिमांशु शेखर, आयोग के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने उन प्रस्तुतियों को दोहराया है जिन्हें चुनौती के तहत निर्णय में स्वीकार किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि शर्त संख्या 13 चयन की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग थी और

उक्त शर्त का अनुपालन न करने से उम्मीदवार को राज्य में अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के रूप में स्थिति का दावा करने से वंचित कर दिया जाएगा। एक स्पष्ट प्रश्न के लिए कि क्या अपीलकर्ता यह दावा करने का हकदार होगा कि वह उक्त आरक्षित श्रेणी से संबंधित है यदि एक नियमित पदोन्नति जारी थी, तो विद्वान वकील एफ ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि वह निश्चित रूप से इतना हकदार होगा।

16. पंकज कुमार[2], के मामले में अपीलकर्ता के पिता जिला पटना के थे (जो पुनर्गठन के बाद अब उत्तराधिकारी बिहार राज्य का हिस्सा है लेकिन हजारीबाग (जो अब झारखंड राज्य का हिस्सा है) में रहता था, जहां अपीलकर्ता का जन्म हुआ था। अपीलकर्ता को 21.12.1999 को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और पुनर्गठन के बाद, उसकी सेवा झारखंड राज्य को आवंटित की गई थी। एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए, वह संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में अनुसूचित जाति श्रेणी के सदस्य के रूप में उपस्थित हुए, और हालांकि उनका नाम एससी श्रेणी के लिए आरक्षित 17 रिक्तियों के मुकाबले क्रम संख्या 5 पर दिखाई दिया, उन्हें इस आधार पर नहीं चुना गया कि वह पटना के स्थायी निवासी हैं, उन्हें झारखंड राज्य में प्रवासी माना जाएगा।

इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, विचार के लिए जो प्रश्न उठे वे इस प्रकार थे:

"46. तत्काल अपीलों में हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उभरता है वह यह है कि क्या कोई व्यक्ति, जो बिहार राज्य का निवासी रहा है और जहां संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 जातियों/जनजातियों की पहचान करता है, पूरे एकीकृत राज्य बिहार में एससी/एसटी के सदस्यों को लाभ प्रदान करता है, जिसे बाद में एक वैधानिक साधन के आधार पर विभाजित किया गया था, अर्थात् अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अंतर्गत विधायी अधिनियमन द्वारा संरक्षित सीमा तक अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अर्थात् अधिनियम, 2000 के दो उत्तरवर्ती राज्यों (बिहार राज्य और झारखण्ड राज्य) में स्थापित अधिनियम, 2000 को अभी भी उत्तरवर्ती राज्य का प्रवासी माना जा सकता है जिससे उन्हें उनके विशेषाधिकारों और लाभों से वंचित किया जा सकता है जिनका लाभ पदधारी अथवा उनके वंशजों ने राष्ट्रपति के आदेश 1950 के प्रारंभ से ही उठाया है बिहार के एकीकृत राज्य में।

इसके बाद, अधिनियम की धारा 73 और 74 के प्रभाव पर विचार किया गया और यह देखा गया:

"49. अधिनियम 2000 की योजना में कहा गया है कि जो कर्मचारी बिहार राज्य में नियत तारीख को या उससे पहले तुरंत काम कर रहे हैं, उनके पास या तो उन जिलों का अधिवास है जो अधिनियम की धारा 3 के तहत झारखंड राज्य का हिस्सा बने हैं या अपनी संबंधित वरिष्ठता में कनिष्ठ होने का विकल्प चुना है या शामिल हुए हैं, झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में और एक वैधानिक साधन के आधार पर अवशोषित हो गए हैं, उनकी सेवा शर्तें सुरक्षित हैं और वे उन विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने के हकदार बन गए हैं जिनके लिए समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रपति आदेश, 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हकदार हैं।

50. इस न्यायालय ने, विवाद की लगभग एक समान प्रकृति की जांच करते हुए सुधाकर विट्ठल कुम्भारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (9) एससीसी 481 के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया -

"5. लेकिन जो प्रश्न यहां विचार के लिए उठता है, वह किसी अन्य मामले में नहीं उठाया गया प्रतीत होता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को असुविधाएं झेलनी पड़ी हैं और कई राज्यों में उन्हें विकास और वृद्धि के लिए सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ आरक्षण के रूप में रक्षात्मक वरीयताओं, सुविधाओं और लाभों की आवश्यकता होती है ताकि वे समुदाय के अधिक लाभप्राप्त और विकसित वर्गों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति है जिसे हल्बा/हल्बी जो मध्य प्रदेश में दोनों को मान्यता प्राप्त है। राज्य के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य के छिंदवाड़ा क्षेत्र में स्थित है, जिसका एक भाग राज्यों के पुनर्गठन के बाद महाराष्ट्र राज्य में आया है, आरक्षण के लाभ के हकदार थे। यह कहना एक बात है कि अभिव्यक्ति "उस राज्य के संबंध में" भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में होती है को प्रभावी या उचित अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि इस संभावना को बाहर किया जा सके कि एक जनजाति जिसे संविधान के प्रयोजन के लिए राज्यपाल से परामर्श करने के बाद एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है, उसे दूसरे राज्य में समान लाभ नहीं मिल सकता है जिसके राज्यपाल से परामर्श नहीं किया गया है; लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि जब किसी क्षेत्र में सदस्यों का वर्चस्व होता है एक ही क्षेत्र से संबंधित एक ही जनजाति जिसे विभाजित किया गया है, सदस्यों को समान लाभ प्राप्त नहीं होंगे जब उक्त जनजाति दोनों राज्यों में मान्यता प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, जो प्रश्न पूछा जाना और उत्तर दिया जाना अपेक्षित है वह यह होगा कि क्या अनुसूचित

जनजाति के सदस्य एक क्षेत्र से संबंधित हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार इसके विभाजन के बावजूद समान लाभ प्राप्त करना जारी रखेगा। देश के किसी विशेष क्षेत्र को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के संबंध में यह पता लगाने के लिए एक ऐसा मामला है जिसकी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है कि दोनों पंधुर्ण जिले में छिंदवाड़ा और चंद्रपुर के क्षेत्र का एक हिस्सा एक ही क्षेत्र और संविधान के तहत था। (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 जैसा कि यह मूल रूप से खड़ा था, उस क्षेत्र की जनजाति हल्बा/हल्बी को समान संरक्षण दिया जा सकता है। इस प्रकार के मामले में, विनिर्देश के लिए इनपुट का गठन करने वाले विभिन्न तत्वों के नुकसान की डिग्री पूरी तरह से अलग नहीं हो सकती है और महाराष्ट्र राज्य पुनर्गठन के बाद भी उक्त जनजाति हल्बा/हल्बी को महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने के लिए सहमत हो सकता है, उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए।

51. यह एक ऐसा मामला था जहां व्यक्ति अनुसूचित का सदस्य था जनजाति को हल्बा/हल्बी के नाम से जाना जाता है। जनजाति की उत्पत्ति जिले में हुई थी। छिंदवाड़ा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश राज्य का एक भाग है, छिंदवाड़ा स्थान चंद्रपुर जिले का एक भाग है, राज्यों के पुनर्गठन पर, मध्य प्रदेश राज्य से मौजूदा महाराष्ट्र राज्य में आया, इसे मध्य प्रदेश राज्य से महाराष्ट्र राज्य में प्रवास का मामला नहीं माना गया। लेकिन महाराष्ट्र राज्य मौजूदा राज्य होने के नाते और विभिन्न तत्वों के नुकसान की डिग्री महाराष्ट्र सिटी बोर्ड के राज्य द्वारा उठाई जा रही आपत्ति पर भिन्न हो सकती है, जहां अवलंबी कार्यरत था, इसे कुमारी माधुरी पाटिल और अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त में इस न्यायालय के एक निर्णय के अनुसरण में गठित और स्थापित जांच समिति द्वारा जांच के लिए खुला छोड़ दिया गया था। जनजातीय विकास और अन्य, 1994 (6) एससीसी 241।

52. झारखंड राज्य के वकील द्वारा किए गए निवेदनों में एक बुनियादी विरोधाभास है कि पदोन्नति संवर्ग पद में आरक्षण के लाभ सहित मौजूदा सेवा शर्तों को उसके नुकसान के लिए अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे खुली/सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सार्वजनिक रोजगार में भाग लेते समय झारखंड राज्य का प्रवासी माना जाएगा और पड़ोसी राज्य में आरक्षण का लाभ लेने के लिए कहा जाएगा। बिहार द्वारा झारखंड राज्य की सेवा का सदस्य बनने के बाद अपने मूल राज्य झारखंड में अलग दर्जा धारण करना, राज्य में नियत दिन अर्थात् 15 नवंबर, 2000 को और उसके बाद पर्याप्त लंबे समय तक सेवा करना कानून में अरक्षणीय है और अधिनियम, 2000 की योजना का उल्लंघन है।

53. यह उनके हित के लिए अत्यधिक अनुचित और हानिकारक होगा यदि विशेषाधिकारों और उनके प्रवाहित लाभों के साथ आरक्षण के लाभों को झारखण्ड राज्य में संरक्षित नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह अधिनियम, 2000 की धारा 73 के आधार पर अवशोषित हो जाता है जो स्पष्ट रूप से न केवल मौजूदा सेवा शर्तों की रक्षा करने के लिए है बल्कि आरक्षण और विशेषाधिकारों का लाभ जो वह नियत दिन को या उससे पहले ले रहा था, झारखण्ड राज्य में सेवा का सदस्य बनने के बाद बिहार राज्य में 15 नवम्बर, 2000 से 15 नवम्बर, 2000 तक कोई हानि नहीं हुई।

54. अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के सामूहिक पठन से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके उद्गम/अधिवास का स्थान नियत दिन या उससे पहले बिहार राज्य का था, अब उन जिलों/क्षेत्रों के भीतर आते हैं जो अधिनियम की धारा 3 के तहत एक उत्तराधिकारी राज्य बनाते हैं, अर्थात, झारखंड राज्य, 2000 से 2000 रुपये झारखंड राज्य के साधारण निवासी बन गए, साथ ही, जहां तक वे कर्मचारी जो बिहार राज्य में नियत दिन अर्थात 15 तारीख को या झारखंड राज्य का हिस्सा बनने वाले जिले में से किसी एक का अधिवास, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपना विकल्प प्रस्तुत किया है या कर्मचारी जो भारत सरकार की नीति के अनुसार अपनी वरिष्ठता के कैडर में कनिष्ठ हैं, जिसका संदर्भ दिया गया है, या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से सेवा करने के लिए बुलाता है (झारखंड राज्य की मौजूदा सेवा शर्तों के संबंध में उनकी मौजूदा सेवा शर्तों में उनके अहित के लिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा और अधिनियम, 2000 की धारा 73 के आधार पर संरक्षित है।

55. हमारे विचार में, ऐसे कर्मचारी जो एससी/एसटी/ओबीसी के सदस्य हैं जिनकी जाति/जनजाति को अधिसूचित किया गया है संविधान (अनुसूचित जाति) में संशोधन द्वारा/(अनुसूचित जनजाति) अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत आदेश 1950 या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के सदस्यों के लिए अलग अधिसूचना द्वारा, विशेषाधिकारों और उनके प्रवाहित लाभों सहित आरक्षण के लाभ, सभी के लिए अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर संरक्षित रहेंगे व्यावहारिक उद्देश्य जो सार्वजनिक रोजगार में भागीदारी के लिए दावा किया जा सकता है (उनके बच्चों सहित)।

56. यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति बिहार के उत्तरवर्ती राज्य या बिहार राज्य में से किसी एक में आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार है। झारखंड आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा एक साथ दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में और जो आरक्षित श्रेणी

के सदस्य हैं और बिहार के उत्तराधिकारी राज्य के निवासी हैं, झारखंड राज्य में खुले चयन में भाग लेने वाले को प्रवासी माना जाएगा और आरक्षण के लाभ का दावा किए बिना सामान्य श्रेणी में भाग लेने के लिए खुला होगा और इसके विपरीत।

57. हमारा विचार है कि वर्तमान अपीलकर्ता पंकज कुमार सिविल अपील @ एसएलपी (सिविल) संख्या 13473/2020, अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर झारखंड राज्य में एक सेवारत कर्मचारी होने के नाते, सार्वजनिक रोजगार की मांग करने वाली खुली प्रतियोगिता में भागीदारी सहित सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति श्रेणी के सदस्यों को स्वीकार्य विशेषाधिकारों और लाभों सहित आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार होगा।

17. जैसा कि 1999 के निर्णय में स्पष्ट किया गया है पंकज कुमार[2] , ऐसे कर्मचारी जो पुनर्गठन के बाद उत्तराधिकारी राज्य के तहत सेवा का विकल्प चुनते हैं, उनकी मौजूदा सेवा शर्तों में उनके नुकसान के लिए परिवर्तन नहीं होगा और अधिनियम की धारा 73 के आधार पर संरक्षित माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस शर्त के अधीन कि ऐसा व्यक्ति दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में एक साथ आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा, ऐसे कर्मचारी न केवल उस उत्तरवर्ती राज्य की सेवा में आरक्षण के लाभ का दावा करने के हकदार होंगे जिसे उन्होंने चुना था और आबंटित किया गया था, बल्कि वे आरक्षण के लाभ के साथ किसी अनुवर्ती खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के भी हकदार होंगे।

18. यह कहा जाना चाहिए कि में निर्णय पंकज कुमार[2] इस न्यायालय द्वारा 19.8.2021 को निर्णय दिया गया था, जबकि वर्तमान में चुनौती के तहत निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा 12.5.2021 को दिया गया था। इस प्रकार उच्च न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय का लाभ नहीं मिला। कानून में तय किया गया है पंकज कुमार[2] , अपील के तहत निर्णय को निर्णय के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए पंकज कुमार[2] . इसलिए यह महत्वहीन होगा कि सीमित विभागीय परीक्षा की प्रकृति को सीधी भर्ती के रूप में लिया जाना है या नहीं, जैसा कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पाया गया है।

19. हालांकि, इस मामले में स्पष्टता के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरक्षण के लाभ का दावा सीमित विभागीय परीक्षा में अगले उच्च स्तर पर पदोन्नति के उद्देश्य से किया गया था। अत इस तरह की सीमित विभागीय परीक्षा के स्वरूप पर विचार करना प्रासंगिक होगा और खुले बाजार से सीधी भर्ती की तुलना में यह क्या हासिल करना चाहती

है, जहां एक व्यक्ति जो संबंधित सेवा का हिस्सा नहीं था, को अपनी उम्मीदवारी की पेशकश करने और पहली बार किसी राज्य के अधीन सेवा में प्रवेश करने का मौका मिलता है। सीमित विभागीय परीक्षा उन व्यक्तियों के लिए एक अवसर प्रदान करती है जो पहले से ही निचले स्तर पर सेवा में हैं और योग्यता के आधार पर त्वरित पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं ऐसे उम्मीदवारों की। ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[3], इस मुद्दे पर कंडिका 27 और 28 में निम्नानुसार विचार किया गया था:

"27. एक अन्य प्रश्न जो विचारणीय है, वह उच्चतर न्यायिक सेवा के संवर्ग यानी जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के पदों पर भर्ती की विधि है। वर्तमान में, उच्चतर न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए दो स्त्रोत हैं, नामित अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा। वही अधीनस्थ न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली की इमारत की नींव है। इसलिए, किसी भी अन्य नींव की तरह, यह जरूरी है कि इसे जितना संभव हो उतना मजबूत होना चाहिए। न्यायिक प्रणाली का भार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका पर टिका हुआ है। जबकि हमने शेट्टी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमानों में वृद्धि होगी, इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारी, जो परिश्रमी होते हुए भी अधिक दक्ष हों। यह जरूरी है कि वे कानून और नवीनतम घोषणाओं के ज्ञान से अवगत रहें, और यही कारण है कि शेट्टी आयोग ने न्यायिक अकादमी स्थापना की सिफारिश की है, जो बहुत आवश्यक है। साथ ही, हमारा यह मत है कि उन अधिकारियों के लिए कतिपय न्यूनतम मानक होने चाहिए जिन्हें अपर जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के रूप में उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रवेश करना है। जबकि हम शेट्टी आयोग से सहमत हैं कि भर्ती उच्चतर न्यायिक सेवा अर्थात् अधिवक्ताओं में से जिला न्यायाधीश संवर्ग के लिए 25 प्रतिशत होना चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया लिखित और मौखिक दोनों प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होनी चाहिए, हमारा विचार है कि उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता के परीक्षण की एक वस्तुनिष्ठ पद्धति होनी चाहिए। और भी अपेक्षाकृत कनिष्ठ और अन्य अधिकारियों के बीच सुधार करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहन भी होना चाहिए ताकि उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके और शीघ्र पदोन्नति प्राप्त की जा सके। इस तरह, हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की क्षमता में और सुधार होगा। इसे प्राप्त करने के लिए, जबकि उच्चतर न्यायिक सेवा में 75 प्रतिशत नियुक्ति का अनुपात पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा बनाए रखा जाता है, तथापि, हमारा यह मत है कि जहां तक पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का

संबंध है, दो पद्धतियां होनी चाहिए उच्चतर न्यायिक सेवा में कुल पदों का 50 प्रतिशत योग्यता-सह-ज्येष्ठता के सिद्धांत के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालयों को उन उम्मीदवारों के कानूनी ज्ञान का पता लगाने और जांच करने और केस-लॉ के पर्याप्त ज्ञान के साथ उनकी निरंतर दक्षता का आकलन करने के लिए एक परीक्षण तैयार करना और विकसित करना चाहिए। सेवा में शेष 25 प्रतिशत पदों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा जिसके लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के रूप में योग्यता सेवा पांच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों को इस संबंध में एक नियम बनाना होगा।

28. पूर्वोक्त के परिणामस्वरूप, पुनरावृत्ति करने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि उच्चतर न्यायिक सेवा में भर्ती अर्थात जिला न्यायाधीशों का संवर्ग होगा:

(1) (क) योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ प्रभाग) में से पदोन्नति और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करके 50 प्रतिशत;

(ख) सिविल न्यायाधीशों की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत (सीनियर डिवीजन) जिसमें पांच साल से कम की योग्यता सेवा नहीं है; और

(ग) 25 प्रतिशत पद संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर पात्र अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(2) उच्च न्यायालयों द्वारा यथाशीघ्र उपरोक्तानुसार समुचित नियम विरचित किए जाएंगे।

(महत्व दिया)

20. बहुत ही प्रकृति से, अगले उच्च स्तर पर पदोन्नति उन लोगों से और उनके बीच होती है जो सेवा में निचले स्तर पर हैं। पदोन्नति का अवसर खुले बाजार के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है, जो सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतिभा प्राप्त की जानी है। उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए एक चैनल के रूप में पदोन्नति केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो पहले से ही सेवा से संबंधित हैं। सामान्य परिस्थितियों में, पदोन्नति उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता से जुड़ी योग्यता की अवधारणा के अनुसार होगी। मेधावी अभ्यथयों, जो सेवा में तुलनात्मक रूप से कनिष्ठ हो सकते हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए सीमित विभागीय परीक्षा

के माध्यम से अवसर की एक खिड़की खोली जाती है। जो लोग परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वे त्वरित पदोन्नति के हकदार हैं। इस प्रक्रिया से आंदोलन का स्वरूप उच्च पद पर नहीं बदलता और यह प्रचारक चैनल बना रहता है। इसलिए उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश रिट याचिका की अनुमति देने का अधिकार। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से रेखांकित भाग यह दर्शाता है कि मामले पर सही परिपे्रक्ष्य में विचार किया गया था। उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ का यह निष्कर्ष न्यायोचित नहीं था कि सीमित विभागीय परीक्षा और कुछ नहीं बल्कि खुले बाजार से सीधी भर्ती थी।

21. इससे पहले कि हम अलग हों, हमें कुछ टिप्पणियों से निपटना चाहिए पंकज कुमार[2]।

22. तत्काल मामले में और के मामले में पंकज कुमार[2], अपीलकर्ता एक विशेष समुदाय या जनजाति से संबंधित थे जिसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया था जब उन्होंने पूर्ववर्ती बिहार राज्य में लोक सेवा में प्रवेश किया। दोनों मामलों में अपीलकर्ताओं को झारखंड राज्य के तहत सेवा के लिए आवंटित किया गया था, हालांकि वे उन क्षेत्रों से संबंधित थे जो पुनर्गठन के बाद अब बिहार के उत्तराधिकारी राज्य का हिस्सा हैं। अधिनियम की धारा 73 और 74 के आधार पर, वे निश्चित रूप से झारखंड के नए गठित राज्य के तहत सेवा में लाभ का दावा कर सकते हैं मे पंकज कुमार[2] में लिए गए दृष्टिकोण के बल पर। झारखंड राज्य में नई सेवा में पात्रता के साथ-साथ वर्तमान मामले में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार, झारखंड राज्य में सीमित विभागीय परीक्षा में पात्रता निश्चित रूप से बनती है। उनकी हकदारी का आधार मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 73 और 74 के कारण है। यह बिल्कुल संभव है कि ऐसे व्यक्तियों की संतानें वापस रह सकती हैं या बाद में अपनी जड़ों की ओर वापस जाने का फैसला कर सकती हैं, अर्थात उस क्षेत्र में जो अब बिहार के नए नक्काशीदार राज्य में आता है; और चूंकि उनकी वंशावली उस क्षेत्र और राज्य से है, इसलिए वे यह तर्क दे सकते हैं कि वे बिहार के नए गढ़े गए राज्य में आरक्षण के लाभों के हकदार हैं, जिस राज्य के संबंध में वे समुदाय से संबंधित हैं, वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति है। पंकज कुमार[2] में निर्णय के अनुच्छेद 55 केवल झारखंड राज्य में अपीलकर्ताओं के वार्डों अथवा संतानों को पात्रता प्रदान करने के रूप में पढ़े जाने में सक्षम है, जहां उनकी वंशावली के विपरीत वे केवल अपने माता-पिता (माता-पिताओं) और अधिनियम के उपबंधों के प्रभाव के माध्यम से संबंध होने का दावा कर सकते हैं।

23. यह कहा जाना चाहिए कि झारखंड राज्य में अपीलकर्ता की संतान या संतान की पात्रता सख्ती से विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुई थी पंकज कुमार[2] . हमारे विचार में, मुद्दा, यदि कोई हो, तो एक उपयुक्त मामले में विस्तार से जाना चाहिए।

24. इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं और 22 सितम्बर,2017 के निर्णय और आदेश को बहाल करते हैं जो उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था। कोई लागत नहीं।

एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ति

मैंने जस्टिस यूयू ललित के फैसले को पढ़ा है और उनके तर्क और निष्कर्षों से सहमत हूं। इसके अलावा, कुछ अन्य कारण हैं, जो मुझे लगता है कि इस मामले के संदर्भ में आवश्यक हैं, और ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इसके बाद उन कारणों के साथ आगे बढ़ता हूं।

संविधान के निर्माता जाति और अन्य कारकों के कारण भारतीय समाज के भीतर मौजूदा विभाजन के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। सहस्राब्दियों पुरानी स्तरित जातिगत वास्तविकताएं, जिनके परिणामस्वरूप पीढ़ियों से समाज के वर्गों का शोषण और उत्पीड़न हुआ था, को संविधान के माध्यम से नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसे हमने खुद पर दे दिया। समाज को समतामूलक बनाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारतीय संविधान विस्तृत प्रावधान करता है – न केवल समानता के अधिकार की घोषणा करके, जो कि हर लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है – बल्कि यह सुनिश्चित करने के प्रावधान भी करता है कि तत्कालीन उत्पीड़ित वर्गों या नागरिकों के वर्गों को लाभ दिए जाएं जो समाज और शासन में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत विशेष उपबंध करने के अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहचान की पद्धति का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ये प्रावधान यह भी निर्देश देते हैं कि राष्ट्रपति के आदेशों में कोई भी परिवर्तन या संशोधन (प्रारंभ में वर्ष 1950 में जारी) केवल भविष्य के संसदीय अधिनियमों के माध्यम से हो सकता है और किसी अन्य माध्यम से नहीं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्यों के भीतर स्थानीय प्रभाव और पूर्वाग्रह प्रबल न हों।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष सुरक्षा उन क्षेत्रों की सुरक्षा में भी प्रकट होती है जिनमें वे निवास करते हैं, जैसे कि पांचवीं और छठी अनुसूचित क्षेत्र।

जबकि ऐसा है,यह भी एक वास्तविकता है कि हमारा देश अविनाशी राज्यों का राष्ट्र नहीं है - इसे अक्सर विनाशकारी राज्यों के एक अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब कभी समाज के वर्गों द्वारा मांग की जाती है, जो स्थानीय आकांक्षाओं के कारण पृथक राज्यों की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो संसद, संबंधित राज्य के परामर्श से अपनी निर्वाचित सभाओं के माध्यम से, कानून द्वारा राज्यों के पुनर्गठन को प्रभावित करती है। इस पुनर्गठन में अनिवार्य रूप से पहले से मौजूद व्यवस्थाओं को बाधित करने का प्रभाव पड़ता है। इस मुकदमेबाजी में हम व्यवधान से चिंतित हैं। पूर्ववर्ती बिहार राज्य में मौजूदा कर्मचारियों और अधिकारियों के सेवा लाभों के संबंध में, जिसे 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा विभाजित किया गया था, और प्रतिवादी पर इसका प्रभाव।

4. संविधान दोनों में "के संबंध में" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है के अवधारण की विधि विहित करते हुए अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंधों को अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संविधान के प्रयोजनों के लिए। स्वाभाविक रूप से, संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र वह इकाई होनी चाहिए जिसके संबंध में समुदायों के सापेक्ष पिछड़ेपन का निर्धारण किया जाना है ताकि उनमें से एक या कुछ को अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित किया जा सके और अनुसूचित जनजातियां। दूसरे शब्दों में, यह निर्धारित करना कि जिस तरह से 1950 में जारी राष्ट्रपति के आदेश (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के संबंध में) ने समुदायों को अधिसूचित किया है, उससे यह स्पष्ट है कि एक विस्तृत और व्यापक कवायद की गई थी। कुछ में उदाहरणों, समुदायों या जातियों को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, केवल एक राज्य में कुछ जिलों के संबंध में या यहां तक कि कुछ के संबंध में तालुका और अन्य सभी में, यह पूरे राज्यों के संबंध में है।

5. दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान मामला एक ऐसे मुद्दे पर प्रकाश डालता है जो उलझता है। दो मुद्दे: एक तरफ, एक निश्चित निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में एक समुदाय का निर्धारण, यह देखते हुए कि क्षेत्र या क्षेत्र संविधान द्वारा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की एक इकाई के रूप में निर्धारित किया गया है;

दूसरा विभाजन या पुनर्गठन के माध्यम से राज्यों के राजनीतिक विभाजन की वास्तविकता है (जैसा कि संसद ने इसे व्यक्त करने के लिए चुना है), जिसमें कई बार अवसर दिया गया है। पुनर्गठन की स्थिति में फिर क्या होता है? पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य के बड़े क्षेत्र के भीतर रहने वाली जाति या समुदाय के अनुसूचित जाति के रूप में नामित सदस्यों को पुनर्गठन के समय विभाजन की स्थिति में व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। जहां पुनर्गठन अधिनियमों में यह प्रावधान है कि संबंधित जाति या समुदाय दोनों राज्यों के संबंध में अधिसूचित जाति या समुदाय बना रहेगा, वहां न्यूनतम व्यवधान होगा। हालांकि, जहां एक अविभाजित राज्य में एक जाति या समुदाय, विभाजन पर द्विभाजित राज्यों में से एक के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता है, जिसके भीतर समुदाय का संबंधित सदस्य रहता है या काम करता है, समस्याएं अनिवार्य रूप से उत्पन्न होंगी।

6. जैसा कि बताया गया है, न्यायमूर्ति ललित के फैसले से, इस समस्या को 1995 में संबोधित किया गया था। पंकज कुमार बनाम झारखंड राज्य और अन्य[1]। जहां अदालत ने निम्नलिखित शब्दों में इस पर चर्चा की:

"52. झारखंड राज्य के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों में एक मौलिक विरोधाभास है कि पदोन्नति कैडर पद में आरक्षण के लाभ सहित मौजूदा सेवा शर्तों को उसके नुकसान के लिए अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे खुली/सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सार्वजनिक रोजगार में भाग लेते समय झारखंड राज्य का प्रवासी माना जाएगा और पड़ोसी में आरक्षण का लाभ लेने के लिए कहा जाएगा बिहार राज्य में झारखंड राज्य की सेवा का सदस्य बनने के बाद अपने मूल राज्य झारखंड में अलग-अलग दर्जा धारण करना, राज्य में नियत दिन यानी 15 नवंबर, 2000 को और उसके बाद पर्याप्त लंबे समय तक सेवा करना कानून में अरक्षणीय है और अधिनियम 2000 की योजना का उल्लंघन है।

53. यह उनके हित के लिए अत्यधिक अनुचित और हानिकारक होगा यदि विशेषाधिकारों और उसके बहने वाले लाभों के साथ आरक्षण के लाभों को झारखंड राज्य में संरक्षित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वह अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर अवशोषित हो जाता है, जो स्पष्ट रूप से न केवल मौजूदा सेवा शर्तों की रक्षा करने के लिए बल्कि आरक्षण और विशेषाधिकारों के लाभ की रक्षा करने के लिए है जो वह नियत दिन को या उससे पहले आनंद ले रहा था, झारखंड राज्य में सेवा का सदस्य बनने के बाद बिहार राज्य में 15 नवंबर, 2000 को उनके नुकसान के लिए अलग नहीं किया जाना चाहिए।

इससे पहले, इस अदालत को 1996 में इस मुद्दे पर विचार करना था। सुधाकर विट्ठल कुम्भारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य[2] जहां समस्या थी जिसे ध्वजांकित किया गया, और समाधान निम्नलिखित तरीके से काम करने के लिए छोड़ दिया गया:

"4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 342 में "उस राज्य के संबंध में" स्पष्ट अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए दूसरे राज्य में लाभ नहीं दिया जा सकता है। [अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी कार्रवाई समिति महाराष्ट्र राज्य में जनजातियां और महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। 1994 (1) एससीआर 714 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद बनाम संजय कुमार सिंह 2003 (7) एससीसी 657।

5. लेकिन जो प्रश्न यहां विचार के लिए उठता है, वह किसी अन्य मामले में नहीं उठाया गया प्रतीत होता है। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बहुत सारे राज्यों में विकास और आगे बढने के लिए सामान अवसर नहीं मिला है और ये हाशिये पर हैं; और उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ आरक्षण के रूप में संरक्षात्मक वरीयताओं, सुविधाओं और लाभों की आवश्यकता होती है ताकि वे राज्य के अधिक लाभप्रद और विकसित वर्गों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें। प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता एक अनुसूचित जनजाति है जिसे हल्बा/हल्बी के नाम से जाना जाता है, जिसे मध्य प्रदेश राज्य के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य में भी मान्यता प्राप्त है, जिसका मूल राज्य छिंदवाड़ा क्षेत्र, जिसका एक हिस्सा, राज्यों के पुनर्गठन पर महाराष्ट्र राज्य में आरक्षण के लाभ का हकदार था? यह कहना एक बात है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में आने वाली अभिव्यक्ति "उस राज्य के संबंध में" को एक प्रभावी या उचित अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि इस संभावना को बाहर किया जा सके कि एक जनजाति जिसे एक राज्य के बाद अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है के प्रयोजन के लिए राज्यपाल के साथ परामर्श संविधान को अन्य राज्यों में समान लाभ नहीं मिल सकता है जिनके राज्यपाल से परामर्श नहीं किया गया है; लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि जब एक ही क्षेत्र के एक ही क्षेत्र से संबंधित एक ही जनजाति के सदस्यों का प्रभुत्व होता है जिसे विभाजित किया गया है, जब उक्त जनजाति को दोनों राज्यों में मान्यता प्राप्त हो जाती है तो सदस्यों को समान लाभ प्राप्त नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, जो प्रश्न पूछा जाना और उत्तर दिया जाना अपेक्षित है वह यह होगा कि क्या एक क्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विभाजन के बावजूद समान लाभ

मिलते रहेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्या देश के किसी विशेष क्षेत्र को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता थी, इस मामले की विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में पांढुर्ना और चंद्रपुर के क्षेत्र का हिस्सा दोनों एक ही समय में एक ही क्षेत्र के थे और संवैधानिक अनुसूचित जनजाति के अधीन थे। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति हल्बा/हल्बी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।

7. एक अन्य निर्णय में, झारखंड राज्य बनाम भदेय मुंडा[3] तर्क यह था कि पुनर्गठन पर, नए पुनर्गठित राज्य में पदोन्नति की संभावना कम थी, और परिणामस्वरूप, अधिकारी को संरक्षित किया जाना चाहिए। इस अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया है:

"जो कुछ प्रस्तुत किया गया था (पहली बार और वह भी मौखिक रूप से) यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार राज्य में मौजूद आरक्षण प्रतिशत झारखंड राज्य में अलग-अलग था, जिससे उनकी पदोन्नति की संभावना कम हो गई थी।

इस अदालत ने 1995 में दिए गए पुराने फैसले का पालन किया। मैसूर राज्य बनाम जी. बी. पुरोहित[4] उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि पदोन्नति की संभावनाओं में परिवर्तन सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं है।

8. मेरी राय में, यह देखते हुए कि किसी समुदाय या जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाना है, यह निर्धारण किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में है (यानी, यह मुख्य रूप से जन-केंद्रित है मौजूदा भू-राजनीतिक के लिए जब यह निर्धारण किया जाता है कि पुनर्गठन की स्थिति में कोई विशेष समुदाय ऐसे राज्य से संबंधित है, तो संसद का कर्तव्य है कि वह स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से स्पष्टता प्रदान करे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में स्थापित कानून यह है कि एक राज्य के संबंध में किसी जाति या जनजाति से संबंधित स्थिति उस समुदाय के सदस्य के बाद लागू नहीं होगी। आदेश 1950 जैसा कि मूल रूप से उस क्षेत्र की जनजाति हल्बा/हल्बी को समान संरक्षण दिया जा सकता है। इस प्रकार के मामले में, विनिर्देश के लिए इनपुट का गठन करने वाले विभिन्न तत्वों के नुकसान की मात्रा पूरी तरह से अलग नहीं हो सकती है और महाराष्ट्र राज्य पुनर्गठन के बाद भी उक्त को शामिल करने के लिए सहमत हो सकता है दूसरे के पास जाता है, (के मुताबिक मैरी चंद्रशेखर राव बनाम डीन सेठ जीएस

मेडिकल कॉलेज[5] और महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी कार्य समिति और महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी कार्य समिति के गठन के संबंध में गठित की गई है बनाम भारत संघ और अन्य[6]। इस अर्थ में, एक व्यक्ति - जो पूर्ववर्ती एकीकृत राज्य से संबंधित था - लेकिन किसे सहमत होना है, किसी भी कारण से, द्विभाजित राज्य में बसने के लिए, एक जगह या क्षेत्र में जहां वह मूल रूप से नहीं रहता था, है अनभिप्रेत . ऐसी स्थितियों को पूरा करने के लिए एक प्रावधान किया गया था, जो स्पष्ट रूप से उन लाभों की रक्षा करता था, जो ऐसे व्यक्तियों को पूर्ववर्ती एकीकृत राज्यों में प्राप्त थे, जैसे कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73, जो पंकज कुमार (ऊपर) से निपटा। इस तरह के प्रावधान अतीत में किए गए थे, और हाल ही में भी।[7]

9. एक अन्य उदाहरण जहां संसद ने व्यवधानों को समायोजित किया है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं, उनकी भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में है - विशेष रूप से यदि वे पांचवीं अनुसूची में वर्णित के रूप में स्थित हैं (भारत का संविधान)। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 42 में निम्नानुसार प्रावधान है:

“42. आरक्षण और अन्य लाभ। – (1) अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध आरक्षण लाभों सहित सभी लाभ और प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां पुनर्वास क्षेत्र में बनी रहेंगी।

(2) कभी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रभावित परिवार, जो पांचवीं अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों या छठी अनुसूची में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, संविधान की अनुसूची को उन क्षेत्रों के बाहर पुनर्स्थित किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे सभी सांविधिक रक्षोपायों, हकदारियों और लाभों को उस क्षेत्र तक विस्तारित किया जाएगा जहां उनका पुनर्वास किया जाता है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पुनर्स्थापना क्षेत्र उक्त में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं। पांचवीं अनुसूची, या उक्त छठी अनुसूची में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्र, या नहीं।

(3) जहां सामुदायिक अधिकारों का निर्धारण अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अधीन किया गया है वहां उनका परिमाण आर्थिक रकम में किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को

ऐसे सामुदायिक अधिकारों में उसके हिस्से के अनुपात में भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित किया जाएगा।

10. मेरी सुविचारित राय में, यह देखते हुए कि राज्यों का पुनर्गठन राजनीतिक मांगों के परिणामस्वरूप होता है, या क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के रूप में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति (यानी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्य) की कोई एजेंसी नहीं है। यह स्थिति एक से मौलिक रूप से अलग है, जहां ऐसे समुदाय का एक सदस्य, स्वेच्छा से अपने या अपने राज्य के बाहर अवसरों की तलाश करता है- जिस स्थिति में, नियम मैरी चंद्रशेखर राव (ऊपर) लागू होगा। परिणामस्वरूप, संसद की ओर से यह दायित्व है कि वह एक तरह की सुरक्षा, ऐसे व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जो नए पुनर्गठित राज्यों में से एक को चुनने के लिए मजबूर हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि पुनर्गठन के परिणामस्वरूप वे बदतर नहीं हैं। एक अलग तरह के अनैच्छिक आंदोलन पर भी विचार किया गया था मैरी चंद्रशेखर राव (ऊपर), जहां इस न्यायालय ने वास्तव में संसद (या संबंधित राज्य विधानसभाओं) को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बच्चों की भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रावधान करने की सिफारिश की थी, जिन्हें सार्वजनिक रोजगार की अपनी शर्तों के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। इसके अलावा, स्पष्टता और सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य, आम तौर पर बोलना सुसंगत होना चाहिए - अर्थात, एक राज्य के पुनर्गठन के मामले में, सुरक्षा दूसरे राज्य के पुनर्गठन के मामले से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 14 और 15 (1) के आदेश को विफल करेगा (यानी, बाद के मामले में, संभवतः जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है)। मेरी राय में, यह कर्तव्य संविधान के भाग I (अनुच्छेद 1 से 4), अनुच्छेद 14, 15 (1), 341 और 342 के सह - संयुक्त पठन से उपजा है, और व्यापक चिंता यह है कि व्यक्ति को बदतर नहीं होना चाहिए, उसके या उसके निर्माण में व्यवधान के कारण। ऐसे मामलों में संसद का कर्तव्य, एक संवैधानिक दायित्व है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति या समूह वंचित न हो।

11. मैं न्यायमूर्ति ललित से सहमत हूं कि पंकज कुमार (ऊपर) जो निर्णय लेने की आवश्यकता से परे चला गया, उसे इसके अनुपात रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसी असंख्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो सीधे निर्णय के लिए उत्पन्न हो सकती हैं- जैसे कि उदाहरण के लिए, जहाँ जाति क को नए पुनर्गठित राज्यों में से एक में अनुसूचित जाति के रूप में नामित नहीं किया गया है, जहाँ व्यक्ति को स्थान निर्धारण के लिए मजबूर किया

जाता है; या जहां संबंधित व्यक्ति के बच्चे राज्य ए में पढ़ रहे थे, और माता-पिता राज्य में थे (और ऐसा ही जारी रहा) और पूर्व राज्य में, संबंधित जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है-या, यहां तक कि बच्चों को उस राज्य से "संबंधित" के रूप में नहीं माना जाता है, आदि। कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रत्येक स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है । अब तक, तय किए गए मामलों के उदाहरण, अनिवार्य रूप से के संदर्भ में रहे हैं। सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण (अनुच्छेद 16) हालांकि, संभवतः, भविष्य में, अन्य प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें इस अदालत को सावधानीपूर्वक जांच के बिना पूर्व-निर्णय नहीं करने के लिए सावधान रहना चाहिए।

12. मैं जस्टिस ललित की टिप्पणियों और निष्कर्षों से सहमत हूं, इसके अलावा, ऊपर वर्णित कारणों से भी।

अपील की अनुमति दी।

<u>यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>